भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1675

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है।

7 श्रावण, 1948 (शक)

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करना

1675. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री विजय कुमार दूबेः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजीलॉकर, उमंग, ई-साइन, डिजिटल लॉकर सेवाओं और अन्य नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्मों से संबंधित पहलों सहित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करने में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है;
(ख) महाराष्ट्र सहित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में डिजिटल गवर्नेंस सेवाओं की पहुंच, अंतर-संचालनीयता और दक्षता में सुधार के लिए सभी मंत्रालयों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
(घ) डिजिटल पहुंच, डिजिटल साक्षरता और डिजिटल समावेशन का विस्तार कर, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल असमानता को समाप्त करने के लिए क्या पहलें की गई हैं; और
(ङ) इन पहलों का देश में, विशेषकर ग्रामीण आबादी, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए जीवन में आसानी, व्यापार करने में सुगमता और डिजिटल सेवा प्रदायगी में सुधार के संबंध में क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित पूरे भारत में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को बढ़ावा दिया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) दृष्टिकोण को अपनाया है, ताकि खुले, परस्पर संचालनीय और विस्तार योग्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जनसंख्या स्तर पर डिजिटल सेवाओं की प्रदायगी को सक्षम बनाया जा सके।

प्रमुख डीपीआई पहल:

सरकार ने पहचान (आधार), भुगतान के लिए (यूपीआई), डेटा एक्सचेंज (डिजिलॉकर और एपीआई सेतु) आदि के लिए जनसंख्या पैमाने पर मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना(डीपीआई) को सफलतापूर्वक

लागू किया है। डीपीआई भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक परिवर्तनकारी शक्ति रहा है, जो वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन, शासन और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि करता है।

डिजिटल सेवाओं में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) – भाषिणी शुरू किया है, जिसकी परिकल्पना भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों के लिए एक सार्वजनिक डिजिटल मंच के रूप में की गई है। भाषिणी मंच भारत की विविध आबादी के लिए संचार बाधाओं को दूर करता है। यह वंचित समुदायों के लिए डिजिटल उपकरणों तक अधिक पहुंच को बढ़ावा देता है।

एपीआई सेतु प्लेटफॉर्म को ओपन एपीआई नीति के कार्यान्वयन की सुविधा और सरकारी सेवाओं के निर्बाध एकीकरण और वितरण को सक्षम करने के लिए एक खुले और इंटरऑपरेबल डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए 8,904 एपीआई एपीआई सेतु प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा, सरकार ने मेरी पहचान, एक सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) प्लेटफॉर्म लागू किया है, जो नागरिकों को एकीकृत प्रमाणीकरण तंत्र का उपयोग करके कई सरकारी अनुप्रयोगों और सेवाओं तक निर्बाध रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है।

डिजिटल इंडिया पहल मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुलभ है, जिसने शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन में सुधार और समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआई का विस्तार करना भारत सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। ये पहल नागरिकों को किसी भी समय और कहीं से भी डिजिटल भुगतान, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, ई-कोर्ट आदि जैसी सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं। सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और अन्य सुविधा चैनलों के माध्यम से सहायता सेवा वितरण, ग्रामीण और संवेदनशील आबादी तक लास्ट-माइल तक सेवा वितरण सुनिश्चित करता है।

कुछ प्रमुख डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थिति जो डिजिटल अवसरंचना को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से ग्रामीण आबादी, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं तक समावेशी और समान पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक रहे हैं, निम्नानुसार हैं:

- **आधार:** आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय-आधारित विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है। अब तक 144+ करोड़ आधार आईडी तैयार की जा चुकी हैं। विभिन्न लोक कल्याण और सुशासन पहल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में लाभार्थी की पहचान के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करती हैं। नामांकन का राज्य-वार विवरण https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/ पर उपलब्ध है ।
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** यूपीआई ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लाखों व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को तीर्व, सुरक्षित और कम लागत वाले डिजिटल भुगतान करने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यूपीआई 55.49 करोड़ से अधिक व्यक्तियों, 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है और 731 बैंकों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन गई है। यूपीआई भारत के 85% डिजिटल भुगतानों और लगभग 50% वैश्विक रियल-टाइम डिजिटल भुगतानों को संचालित

करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार यूपीआई आँकड़े https://www.npci.org.in/product/ecosystem-statistics/यूपीआई पर उपलब्ध हैं ।

- **डिजिलॉकर:** डिजिलॉकर नागरिकों को किसी भी समय मूल जारीकर्ताओं द्वारा जारी प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म में 71.66 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिसमें 2,822 ऑनबोर्ड जारीकर्ताओं द्वारा 936.03 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। पिछले एक वर्ष में, 17.90 करोड़ उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया और 26.74 करोड़ दस्तावेज जारी किए गए। डिजिलॉकर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए महाराष्ट्र राज्य में 4.46 करोड़ से अधिक आधार सक्षम पंजीकरण हुए हैं। राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिए गए है।

- **यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग),** सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन, प्रचालनरत है और व्यक्तियों के लिए 241 विभागों से 2,575+ सेवाएं प्रदान करता है। पिछले एक वर्ष में, 374 सेवाएं ऑनबोर्ड की गईं और 186.24 लेनदेन किए गए। उमंग पर उपलब्ध उपयोगकर्ताओं और डिजिटल सेवाओं का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है और https://web.umang.gov.in/landing/services पर उमंग पोर्टल पर भी उपलब्ध है ।

- **ई-साइन (ई-हस्ताक्षर):** ई-हस्ताक्षर एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, जिसे एक ई-हस्ताक्षर उपयोगकर्ता को डिजिटल रूप से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की सुविधा के लिए एक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से सेवा वितरण अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। ई-हस्ताक्षर सेवा कानूनी रूप से स्वीकार्य रूप में नागरिकों द्वारा दस्तावेजों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है। सभी ई-हस्ताक्षर सेवा प्रदाताओं (ईएसपी) द्वारा कुल 155.56 करोड़ ई-हस्ताक्षर जारी किए गए हैं। सी-डैक द्वारा (अर्थात ई-हस्ताक्षर परियोजना के अंतर्गत) कुल 44.23 करोड़ ई-हस्ताक्षर जारी किए गए हैं। पिछले एक वर्ष में लगभग 12.46 करोड़ ई-हस्ताक्षर जारी किए गए। राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिए गए है।

- **एपीआई सेतु:** एपीआई सेतु परियोजना का उद्देश्य डेटा स्वामियों और अंतर- एवं अंतः-सरकारी एजेंसियों के बीच डेटा के कुशल साझाकरण को बढ़ावा देना है, ताकि सेवाओं को एकीकृत तरीके से प्रदान करने के लिए अंतर-संचालनीय प्रणालियों के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में, पोर्टल ने एपीआई सेतु प्लेटफॉर्म पर कई केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए 8,904 एपीआई प्रकाशित किए हैं।

- **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)** 800 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान करते हैं, जिससे ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से अंतिम-मील सेवा वितरण में वृद्धि होती है। मई 2026 तक, देश भर में 5.01 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर पर 3.91 लाख शामिल हैं। राज्य-वार और जिला-वार विवरण सीएससी पोर्टल पर https://csc.gov.in पर उपलब्ध हैं ।

डिजिटल पहलों का प्रभाव:

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने सुलभ, कुशल और पारदर्शी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर नागरिक सेवा वितरण को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), डिजिलॉकर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), उमंग, कॉमन सर्विस सेंटर

(सीएससी), एपीआई सेतु और मेरी पहचान जैसी प्रमुख डिजिटल पहलों ने सरकारी सेवाओं, डिजिटल भुगतान, डिजिटल दस्तावेजों और लाभों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण तक निर्बाध पहुंच को सक्षम बनाया है।इन पहलों ने कागज रहित, फेसलेस और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देते हुए सेवा वितरण समय, लेनदेन लागत और सरकारी कार्यालयों के दौरे की आवश्यकता को कम किया है। सीएससी के व्यापक नेटवर्क ने विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के लास्ट- माइल तक वितरण को और सुदृढ़ किया है। इन पहलों ने सरकारी सेवाओं, अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक अधिक पहुंच के माध्यम से डिजिटल और वित्तीय समावेशन को बढ़ाया है, जीवन की सुगमता और व्यापार करने में आसानी में सुधार किया है और महिलाओं और वंचित वर्गों सहित नागरिकों को सशक्त बनाया है।

डिजिटल अवसरंचना को सुदृढ़ करना और डिजिटल विभाजन को पाटना:

सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार, डिजिटल सेवा वितरण का विस्तार करके, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर और महाराष्ट्र सहित क्षेत्रीय भाषाओं और नागरिक जागरूकता में सेवाओं तक पहुंच को सक्षम करके विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटने और डिजिटल अवसरंचना को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलें की हैं। इसमे निम्नलिखित शामिल है:

- ग्राम पंचायतों और ग्रामीण संस्थानों के लिए भारतनेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार। जून 2026 तक, देश भर में भारतनेट परियोजना के तहत कुल 2.21 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया गया है। जून 2026 के दौरान, 80,472 ग्राम पंचायतों पर भारतनेट प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) प्रचालनरत हैं।

- दूरसंचार, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच: भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 93.3 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2026 में 133+ करोड़ हो गए। इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2026 में 109.27 करोड़ हो गई।

- सरकार द्वारा वित्त पोषित 4जी संतृप्ति परियोजना और अन्य मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत, जून 2026 तक देश में 24,812 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।

- सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) 800 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान करते हैं, जिससे ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से लास्ट- माइल सेवा वितरण में वृद्धि होती है। मई 2026 तक, देश भर में 5.01 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर पर 3.91 लाख शामिल हैं।

- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। देश भर में कुल 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। यह योजना 31.03.2024 को समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएएमएस), 2022-23 के अनुसार, 15-24 वर्ष की आयु के 78.4% व्यक्तियों ने संलग्न फाइलों के साथ संदेश भेजने की क्षमता की सूचना दी, जो युवाओं के बीच बेहतर डिजिटल कौशल का संकेत देता है। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि 94.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 97.1 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास टेलीफोन/मोबाइल फोन है।

- फ्यूचरस्किल्स प्राइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटीएस), साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी (एआर/वीआर) आदि

जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रदान करता है। कार्यक्रम के तहत, अब तक, 34+ लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 23+ लाख उम्मीदवारों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित/प्रशिक्षित किया गया है।

- इंडियाएआई मिशन के तहत, "इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स" स्तंभ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एआई साक्षरता और क्षमता निर्माण के विस्तार पर केंद्रित है। शिक्षार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम के बीच एआई जागरूकता और मूलभूत साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए "युवा एआई फॉर ऑल" कार्यक्रम जैसी पहल शुरू की गई है। इंडियाएआई मिशन द्वारा पेश किया जाने वाला युवा एआई फॉर ऑल पाठ्यक्रम आईजीओटी कर्मयोगी भारत, फ्यूचरस्किल्स प्राइम, दीक्षा, इंटेलिपाट, खान एकेडमी, कौरसेरा आदि सहित कई डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) देश भर में 56 केन्द्रों और 9,000 से अधिक साझेदार संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से एसीसी और सीसीसी सहित डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

- ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा) सभी ग्रेडों के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जेइज्ड पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में एक भागीदार के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बहुभाषावाद को सक्षम करने वाली स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.67 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और योगदान दिया है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 2.29 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए 579.41 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं।

- सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन सृजित करने और जनता के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा साइबर जागरूकता - सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) कार्यक्रम लागू किया गया है। अब तक, देश भर में 6,650 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें स्कूल/कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन, सरकारी कर्मियों और आम जनता सहित 11.37 लाख+ प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

*****

अनुबंध

उमंग, डिजिलॉकर और ई-हस्ताक्षर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

	परियोजना का नाम	**उमंग**	**डिजिलॉकर**		**ई- हस्ताक्षर**
	संकेतक->	**कार्यान्वित की गई सेवाओं की संख्या**	**आधार सक्षम पंजीकरणों की संख्या**	**एकीकृत किए गए कुल विभाग/ संस्थान**	**जारी किए गए ई- हस्ताक्षरों की संख्या**
क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**				
1	आंध्र प्रदेश	3	19679831	240	111276111
2	अरुणाचल प्रदेश	0	388179	15	1002709
3	असम	405	10619927	57	24920145
4	बिहार	3	28642947	51	75684225
5	छत्तीसगढ़	39	6835233	51	20400705
6	गोवा	26	579659	23	3160904
7	गुजरात	234	20351432	148	88463488
8	हरियाणा	143	11004434	100	42544154
9	हिमाचल प्रदेश	18	2790520	44	8673613
10	झारखंड	39	9294483	49	23578336
11	कर्नाटक	0	28331890	238	156115050
12	केरल	7	11552382	125	39237444
13	मध्य प्रदेश	48	23206090	140	108447956
14	महाराष्ट्र	60	44616860	354	183374483
15	मणिपुर	3	832818	19	2035566
16	मेघालय	13	691888	16	1200829

17	मिजोरम	0	283468	16	944363
18	नागालैंड	0	403942	17	915518
19	ओडिशा	7	11597137	83	37612338
20	पंजाब	8	10108233	55	30364044
21	राजस्थान	11	23473904	138	98269221
22	सिक्किम	14	195100	16	1091432
23	तमिलनाडु	17	21847515	160	127047142
24	तेलंगाना	19	9006198	83	38024737
25	त्रिपुरा	36	1036703	18	4538423
26	उत्तर प्रदेश	91	64515375	143	166810432
27	उत्तराखंड	115	4195692	65	16688695
28	पश्चिम बंगाल	0	23922554	87	73138034
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	35	131075	9	1017546
30	चंडीगढ़	36	570513	18	2993611
31	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	119	10289067	149	51079814
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5	199914	6	1936902
33	लक्षद्वीप	9	19679	4	326347
34	पुडुचेरी	23	427921	15	2291385
35	जम्मू और कश्मीर	105	3790394	37	10330603
36	लद्दाख	4	39029	10	111917

****